[Prof. Madhu Dandavate]
have said. I want to point out to you that when I asked you to make my submission....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are repeating the same thing. (*Interruptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE: Why are you so allergic? I am following the procedure. With your permission.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me point out that, according to the rule, any tedious repetition is not allowed. You are repeating the same thing.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am not repeating. I am making a further point that after your statement, I want to make a further comment that Shri Limaye was very clear in his mind when he got up to say that "Sir, if Shri Naik continues—it is already 5-30—I will have no opportunity to make my statement here." He said that After that you said that 'you may take a few minutes before the next item is taken up' That means you are prepared to permit Shri Madhu Limaye to make a statement even beyond 5-30 and therefore, you should permit him. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please Prof. Dandavate, hear me coolly and calmly. I said: this will not deprive you of this opportunity; your apprehension is unwarranted. I did say that. But, I never said that that will be done within the 5-30 limit. But, what I have in mind is that even if you cannot complete today, this discussion will continue tomorrow and Shri Madhu Limaye will have his full opportunity tomorrow. That is all I say. No rulling on this.

Now, I decide that the House takes up the half-an-hour discussion.

SHRI MADHU LIMAYE: Now, I am on a point of order. (*Interruptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE: You please check up the record of what he said here before you take up the Half-An-Hour discussion.

17.55 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PRINCIPLES OF PARITY BETWEEN THE PRICES OF MANUFACTURED ARTICLES AND AGRICULTURAL PRODUCTS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up the half-an-hour discussion.

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपका यह निर्णय रहा कि इस विधेयक पर जो चर्चा है वह कल तक के लिए टाल दी गई है । आपका यह भी निर्णय रहा कि मुझे स्पष्टीकरण का आपने अधिकार दिया है वह स्पष्टीकरण भी मैं कल करूं । अब मैं केवल इतना ही कहना हूं कि चरित्र-हनन उन्हीं लोगों का होता है जिन के पास चरित्र होता है । इतना कह कर मैं आधे घंटे की बहस पर जा रहा हूं (**इंटरप्शंस**) चरित्र होना चाहिए पहले । कौन सा चरित्र है इन लोगों के पास जिसका हनन हो सकता है ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur): There is nothing before the House until the half-an-hour discussion starts, and, therefore, there can be no point of order on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: A point of order can be raised between the conclusion of one subject and before taking up another subject The hon. Member wants to raise a point of order, and let me listen to his point of order.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: All right, but there is no point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the half-an-hour discussion.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: It is already five minutes, to six O' clock.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): They are determined to obstruct everything that Shri Madhu Limaye says. They have an allergy for Shri Madhu Limaye. Sir, you must control the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. Let Shri Madhu Limaye continue with his half-an-hour discussion.

श्री हुकम चन्द कछवाय : (मुरेना) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । छः बजने में तीन मिनट बाकी हैं । क्या आप तीन मिनट में इसको खत्म करने जा रहे हैं ।

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा शुरू होनी चाहिए थी । अब तीन मिनट बाकी रह गये हैं । आप इसके लिए आधा घंटा देंगे या नहीं देंगे ?

18 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to tell this to Shri Phool Chand Verma and also Shri Hukam Chand Kachwai. Shri Kachwai is an old Member of this House and he has been here for two or three terms and he should know this. But sometimes people forget and they need to be reminded. I shall remind him of this. Shri Phool Chand Verma is a new member, and perhaps he is here for the first time. When we take up the half-an-hour discussion, it means that—from the time that we take it up, it is half an hour. Will he kindly bear this in mind in the future?

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के दामों और कारखानों में जो चीजें बनती हैं, उन के दामों में जो संतुलन का अभाव है, जिस के कारण हिन्दुस्तान के काश्तकार का शोषण होता है, उसके बारे में यह आधे घंटे की बहस उठाना चाहता हूं ।

मंत्री महोदय को जो प्रश्न मैंने भेजा था, उस में मैं ने पूछा था कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि औद्योगिक माल पैदा करने वाले जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, या जापान जैसे देश हैं उन के दामों में और जो कच्चा माल पैदा करने वाले देश हैं, उन को जो दाम मिलते हैं उन में विषम रिश्ता है । (**व्यवधान**)

1801 hrs.

[Shri Sezhiyan in the Chair]

क्या यह हल्ला चलता रहेगा ? (**व्यवधान**) अगर आप व्यवस्था प्रस्थापित नहीं करेंगे तो मैं बोलना नहीं चाहता । (**व्यवधान**) ये हल्ला क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) इस से पता चलता है कि कृषि दामों के बारे में इन को कितनी दिलचस्पी है । ये तो किसानों के शोषक हैं । ये क्या दिलचस्पी लेंगे ?

मैं ने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि औद्योगिक माल पैदा करने वाले देशों और कच्चा माल पैदा करने वाले देशों के व्यापारिक रिश्ते ऐसे हैं कि कच्चा माल पैदा करने वाले देशों का निरन्तर शोषण होता रहा है । उसी तरह हमारे देश में भी कारखानों में जो चीजें बनती हैं, उन के दाम भी निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें मौसम के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है । लेकिन किसान जिन चिजों को पैदा करता है, मौसम के अनुसार उन के दाम बदलते रहते हैं । जैसे, आप धान—चावल-का उदाहरण लीजिए । जब नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में नया चावल आ जाता है और किसान बेचने लगता है, तो दाम गिरने लगते हैं --दामों का षड्यंत्र ऐसा रहता है कि अकसर ऐसा होता है कि ; आप लगातार कई सालों के आंकड़े देख सकते हैं—और जब किसानों के हाथ से माल व्यापारियों, सेठों, के हाथ में चला जाता है, तो दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं ।

एक तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सीजनल फुलक्चुएशन, मौसमी परिवर्तन, के कारण जो काश्तकार मारा जाता है, उस को संरक्षण देने के लिए वह पांचवी पंच वर्षीय योजना में और चालू योजना में कौन सा इलाज करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता

[श्री मधु लिमये]

हूं कि महाराष्ट्र आदि कुछ जगहों मे रुई खरीदने का काम सहयोगी समितियों की मार्फत सरकारी क्षत्र मे होता है । इस लिए रुई के दामों मे मौसम के अनुसार जो उतार चढाव होता है उस से किसानों को ज्यादा ठोकर नही लगती है । लेकिन यदि हम पूरे देश की बात ले ले, तो जितना कच्चा माल पैदा होता है, जो व्यापारिक फसलें पैदा होती है, चाहे वह तम्बाकू हो, या कैस्टर सीड और मूगफली हो या फिर चावल या गेंहू हो उन सब के दाम मौसम के अनुसार गिर जाते है । मन्त्री महोदय पहले इस बात का खुलासा करे कि मौसमी-उतार चढाव से समूचे देश के काश्तकारों को बचाने के लिए यह क्या कर रहे है ।

सरकार ने अभी कहा है कि वह गेहू की खरीद सरकारी क्षत्र मे करेगी और उसके थोक व्यापार को अपने हाथ मे लेगी । सरकार द्वारा इस का दाम 76 रुपये प्रति-क्विंटल तक निर्धारित किया गया है । हवाला एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन का दिया जाता है, लेकिन मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते है कि एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन ने जो दाम निर्धारित किये वे दाम स्पाट प्राइस के रूप मे थे, यानी उसके नीचे गेहू का दाम न जाय । कमीशन की यह इच्छा थी कि अगर दाम उस से नीचे जाय, तो सरकार का फूड कारपोरेशन स्वयं मंडी मे जाकर खरीदने का काम शुरू करे, ताकि दाम उसके नीचे न गिरने पाएं लेकिन चूंकि सारा व्यापार सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है इस लिए प्रोक्योरमैन्ट का दाम और सपोर्ट का दाम एक ही होगा ।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) सभापति महोदय, हाउस मे कोरम नही है ।

SHRI G VISWANATHAN (Wandiwash) Sir, it is a conspiracy on the part of the Treasury Benches This is a most irresponsible attitude (*Interruptions*). There is no question of querum now.

PROF MADHU DANDAVATE: We warn the Treasury Benches that they will find it impossible to conduct the business of the House, if the question of quorum is raised now like this

MR CHAIRMAN: There is a convention, a gentleman's agreement, that after 6 O'clock the question of quorum should not be raised Therefore, I appeal to the hon Members not to raise this. Yes, Mr. Madhu Limaye may continue.

श्री हुकम चन्द कछवाय सदन मे कोरम बनाए रखने के लिए इधर से 15 सदस्य और कांग्रेस के 35, 37 सदस्य होने चाहिए इस समय कांग्रेस के सदस्य कम है । (व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : हाउस मे पार्लियामैन्टरी एफेयर्स के मिनिस्टर भी नही है और डिपुटी मिनिस्टर भी नही है । इन को शर्म आनी चाहिए । (व्यवधान)

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) Sir, will it be unparliamentary to call him a clown?

MR CHAIRMAN Mr Madhu Limaye may continue

श्री मधु लिमये । श्री शंकर दयाल सिंह सदन से माफी मांगे । उन्होंने अडंगेबाजी की है । (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : उधर के माननीय सदस्य हर समय व्यवस्था के प्रश्न उठाया करते है । आज अगर मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, तो क्या मैंने गलत बात की है ? (व्यवधान)

MR CHAIRMAN. Order, please Mr Madhu Limaye, please continue

SHRI P G. MAVALANKAR (Ahmedabad) Sir, may I say that for the last several weeks there have been many occasions when there was no querum but some of us purposely did not raise this matter because we wanted that the matters must be dis-

cussed in the House. If, now, the Member on that side is insisting on quorum, we shall raise it every week and every time when there is no quorum. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: MR. Madhu Limaye will continue his speech. (*Interruptions*) If the hon. Member is insisting upon quorum, I have no option but to ring the quorum bell. Is he insisting on it?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: After your ruling, I will not insist on it, because you said that after 6 O' clock there is a convention not to raise this question of quorum.

MR. CHAIRMAN: There is no ruling from the Chair. The convention is that quorum is not asked for after 6 O' clock. If you insist on a quorum, the Chair will have no option but to ring the bell and see. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): I may just submit that the convention is that after 6 O' clock we do not ask for quorum. If the hon. Member has accepted this position why carry on this controversy?

MR CHAIRMAN: This is no ruling. That is the convention.

SHRI P. G. MAVALANKAR: With all respect to you when the quorum is challenged the Chair has no authority to go against it. It is a constitutional requirement. There must be a quorum now.

MR. CHAIRMAN: That Member is not raising the quorum now. Is any other Member raising the quorum now? I had already pointed out that it is the convention not to raise quorum.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: I accepted your ruling.

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल साफ है कि उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है ?

MR. CHAIRMAN: Are you raising the quorum.

SHRI PHOOL CHAND VERMA: I had not raised the quorum. Mr. Shankar Dayal Singh has raised it

MR. CHAIRMAN: He did not challenge the quorum now. Therefore I am asking Mr. Limaye to continue.

SHRI MADHURYYA HALDAR (Mathurapur): He has raised the point about quorum. Either he should apologise or the quorum should be insisted upon.

MR. CHAIRMAN: Let me explain the position. It is true he raised the quorum and also he said that there was no quorum. Then I explained to him the convention and he sat down.

SHRI P. G. MAVALANKAR: How can there be a convention against the constitution. It is imperative. I want the quorum now.

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य केन्द्रीय हाल में गए, वहां से देख कर आने के बाद उन्होंने यह सवाल उठाया है कोरम का। मैं उनका यह चेलेज स्वीकार करता हू। कल से वह भी हमारा चैलेज स्वीकार करे। कल से रोज हाउस में कोरम की घंटी बजेगी।

SHRI P. M. METHA (Bhavnagar): The quorum is challenged by Mr. Mavalankar. He has very pointedly said that a convention cannot prevail over the constitutional provision. What is your ruling? It is true that there is a convention, but the quorum was challenged by the hon. Member.

SHRI K. C. PANT: I would like to tell Mr. Mavalankar that this was the practice in the olden days also when we used to meet during lunch hour. Then also there was this convention that quorum should not be raised during the lunch hour. But I have known cases where the question of quorum was raised and later on the Chair gave a similar advice as you gave just now that the convention is such and such and the debate has proceeded. Secondly, we are trying to accomodate the opposition in everything and in this matter also, Shri Shankar Dayal Singh is trying to see that the debate is not interrupted. It is in a spirit of goodwill that we are doing it and we hope they will also reciprocate it.

श्री हुकम चंद कछवाय : यदि कोरम चलज किया जाता है तो वापिस नहीं होता है, आज तक वापिस नहीं हुआ ।

SHRI P. G. MAVALANAKAR: I am not able to appreciate the explanation given by the hon. minister. There has to be quorum in this House at any time of the day.

MR. CHAIRMAN: If quorum is challenged, the Chair has no option but to ask that the bell may be rung. In this case, it is true that Mr. Shankar Dayal Singh said, there was no quorum. But afterwards when I pointed out the convention, I think he withdrew it. I want to ask him, again whether he is withdrawing it.

शंकर दयाल सिंह : मैंने कोरम का सवाल उठाया था लेकिन आपने कहा कि छः बज के बाद उसकी जरूरत नहीं होती । तो मैंने आपकी बात को मान लिया । मैंने उस चलज को वापिस ले लिया । उसके बाद बहस को कोई जरूरत नहीं है और आलरेडी हाउस में कोरम है । इस लिए लिमये जी को बोलना है तो बोल और नहीं बोलना है तो कह की नहीं बोलना है ।

श्री मधु लिमये : मैं आपकी कृपा से बोलना नहीं चाहता . .

PROF. MADHU DANDAVATE: We have been observing in this House a tendency that whenever Mr. Madhu Limaye raises to speak on any subject, there is an effort to put obstacles. If this is done, they will get it back fully. (*Interruptions*).

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati): It is not correct. There is no intention on our part to put obstacles. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You please resume your seat. I have counted and there are more than 53 members present in the House. The House is fully constituted. Mr. Limaye may continue. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, माता जी की कृपा से जो लोग आए हैं, वे हम को सिखा रहे हैं, कैसे बोलते हैं . . . . (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Order, order. Please sit down; no interruptions please. There is the Minister to answer. He will asnwer all the valid points. No other Member should interrupt him.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने जो सपोट का दाम निश्चित किया, वही थोक व्यापार हाथ में लेने के बाद, खरीदने का दाम, प्रोक्योरमेंट का दाम बन गया, इससे काश्तकारों के साथ भयंकर अन्याय हुआ । मैं पांच छः सालों से देख रहा हूं ——जहां जापान जैसा देश जो चावल के मामले में स्वावलम्बी नहीं था, उन्होंने मकार्थर के जमाने में वहां ऐसे भूमि सुधार कानून लागू किये कि खेती के मालिकों की संख्या जो पहले 50 प्रतिशत के आसपास थी, मकार्थर रिफार्म के बाद 95 प्रतिशत हो गई और जो टेनेन्टस थे, उन की संख्या जो पहले बहुत ज्यादा थी, 5 प्रतिशत तक नीचे आई । चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने पावर- टिलर बनाए, बड़े पैमाने पर बनाये और किसानों को बहुत सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स, बीज आदि देने

का इंतजाम किया। नतीजा यह हुआ कि जापान का सामराज्य खतम होने के बाद 26 सालों के अन्दर चावल के मामले में जापान स्वावलम्बी बन गया। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि 4 साल पहले फर्टिलाइजर के ऊपर लेवी लगाई गई, उस के बाद दो साल पहले उस लेवी को और बढा दिया गया। पैस्टीसाइड्स के दाम भी बहुत ज्यादा बढ गये। बीज के बारे में क्या कहूं--कल ही एक नेशनल टनेज क्लब नाम की कोई संस्था है, उस के कुछ सदस्य मुझ से मिलने आये थे। और उन्होंने मुझ से कहा कि 50 हजार क्विटल साधारण अनाज खरीद कर बाहर उड़ीसा आदि राज्यों में, अच्छे बीज के रूप में वेचा गया, इस तरह से लूटा गया। यह नेशनल टनेज क्लव, जिस को सरकारी अनुदान मिलता है, मामूली अनाज बीज के रूप में किसानों को वेचने का काम करती है।

इस लिए मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं उन्होने गहूं के लिए जो प्रोक्योरमैन्ट का, खरीदने का दाम निर्धारित किया है और आने वाले खरीफ सीजन में वह चावल के लिए, धान के लिए जो दाम निर्धारित करने जा रहे हैं, उस के बारे में पहले तय करें कि क्या वे चाहते हैं कि हमेशा कृषि घाटे में रहे, किसानों की आमदनी न बढे, किसानों को फर्टिलाइजर बनाने वाली पेस्टीसाइडस बनाने वाले..बीज बेचने वाले हमेशा लूटते रहे? कारखाना में बनने वाली दूसरी सारी चीजों के दाम फर्टिलाइजर की तरह से 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक बढ गये हैं तो कोई संतुलन रहेगा या नहीं ? किसान को जो दाम मिलता है और कारखानों में बनने वाली चीजों के जो दाम हैं--उन में कोई संतुलन रहेगा या नहीं ?

सभापति महोदय, आज कारखानों में जो चीजें बनती हैं वह वर्ग बहुत ज्यादा संगठित है, इतना संगठित है कि वह अगर पैदावार ज्यादा भी हो जायेगी तो सरकार के साथ मिल कर कृत्रिम अभाव पैदा कर देगा, दाम को बढा कर मुनाफा कमायेगा। लेकिन किसान असंगठित है, उस को साहूकार के पास आज भी जाना पड़ता है। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन बैंकों की कर्जा देने की जो नीति है, उस में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। दिखावटी तौर पर बतलाते हैं कि इतने करोड़ दे रहे हैं 9 हजार करोड रुपया बैंकिंग सिस्टम के पास है इन के पास औद्योगिक क्षेत्र में 2 हजार करोड रूपया खर्च करने के लिए है, चाहे निजि क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, लेकिन समूचे देश में एनर्जाइजड पम्पिंग सैटस लगाने का जो जो काम करना चाहिए, उस के लिए इन के पास पैसा नहीं है।

रुई के दाम की चर्चा कई बार हो चुकी है। यहां खाद्य मंत्री शिण्दे साहब बैठे हुए हैं--क्या वे इस बात को काट सकते हैं कि एकाधिकार--खरीद के वावजूद महाराष्ट्र के कास्तकारों को, रूई पैदा करने वालों को पूरा संरक्षण नहीं मिल पाया और जनवरी, 1971 में रूई के जो दाम थे और अप्रैल, 1973 में रूई के जो दाम रहे हैं, उन में 28 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत की कटोती हुई है, लेकिन कपड़े का दाम सूत के दाम के अनुपात में कभी नहीं गिरा। इस लिए इनकी सारी नीतियों का असर हो रहा है और जो पैदावार करने वाला कास्तकार है, उस को लूटने का काम लगातार किया जा रहा है।

मूंगफली की हालत को देखिए--डालडा का दाम लीजिए --किसानों ने जब मूंगफली वेची, तब उनको क्या दाम मिला और इस वक्त तेल का क्या दाम है, आप दोनों की तुलना कीजिए--मेरी बात की पुष्टी हो जायेगी कि किसानों को लूटने का काम किस तरह से हो रहा है।

तम्बाकू की बात लीजिए---तम्बाकू एक ऐसी उपज है जिस को बेच कर विदेशी मुद्रा

[श्री मधु लिमये]

मिलती है । आन्ध्र प्रदेश मे 95 प्रतिशत विर्जीनिया टबैको पैदा होती है, लेकिन अगर 10 रुपये की तम्बाकू निर्यात होगी तो किसान को, जो उसको पैदा करने वाला है, उस को ढाई रुपये भी नही मिलेंगे । आन्ध्र के काश्तकारो से पूछिएं—तम्बाकू के निर्यात का काम कौन करता है—एक विदेशी कपनी जो अमरीकन-ब्रिटिश टबैको कम्पनी के साथ जुडी हुई है ।

कैस्ट्राइल की बात लीजिए—स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने निर्यात का काम अपने हाथ मे ले लिया । जिस का दाम उस समय 5 हजार रुपये था, उस को मिलर्स और शिपर्स को स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ने साढे सात हजार रूपये मे दिया । यदि यह ढाई हजार रुपया आप किसानो को देते तो मेरा कोई झगडा नही था । अकेले रूई के व्यापार मे, मैंने हिसाब लगाया है, किसानो की जेब से 400 करोड रुपया निकल गया .

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) रूई कैंमी कैसी होती है, आप को मालूम भी है कई क्वालिटी की रूई होती है .

श्री मधु लिमये आप को फिगर्स चाहिए ।

श्री सतपाल कपूर कई तरह की रूई होती है, आप को मालूम नही है ।. . (व्यवधान) . . .

MR CHAIRMAN Please do not interrupt (व्यवधान) . . . .

श्री मधु लिमये सत्ता का नशा चढ़ रहा है। मैं इन्ही मदांध लोगो पर अंकुश लगाने का काम करने के लिए यहा आया हूं . . . . .

(व्यवधान) . . . .

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Sat Pal Kapoor. Mr. Madhu Limaye is raising the half-an-hour discussion. Please do not interrupt.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय जिस तरह से कैस्ट्रायल और तम्बाकू का मामला है, उसी तरह सें गन्ने का मामला है. . . (व्यवधान) . .

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि गन्ना उत्पादक जहां सहयोगी समितियों सें संगठित हो गये है तो कुछ उन का बचाव हो रहा है । लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गन्ना उत्पादक हैं, जो ज्यादा सगठित नही हैं, उन लोगो को मिल मालिक बुरी तरह लूट रहे हैं । माननीय चव्हाण ने यह कहा कि पैदावार बढाओ दाम नीचे आ जायेंगे । मैं माननीय शिन्दे साहब से पूछना चाहता हू कि विगत साल की तुलना से इस साल चीनी का दाम बढा हुआ है और चीनी की पैदावार बढी है या नही ? लेकिन चीनी की पैदावार बढते हुए भी चीनी के दाम क्यों नही घटा । चीनी की पैदावार बढते हुए भी चीनी का दाम मे कोई परिवर्तन नही आया, बल्कि चीनी का दाम लगातार बढता जा रहा है । इस लिए मत्री महोदय से मै यह कहूगा

कारखाने मे बनने वाली चीजो और खेती की उपज, दोनो मे सतुलन कायम कीजिए खेती की उपज का दाम निर्धारित करते समय उत्पादन को जो खर्चा है उम का ध्यान रखा जाय । अभी तक कम से कम इन बढे पूजिपतियो की तरह किसान अपनी बुक्स को मैनिपूलेट करना नही जानता है बुक्स तक नही लिखता है इस लिए उत्पादन के के खर्चे का आप लोग विचार नही करते । उत्पादन के खर्चे का विचार कीजिए और कोई क्रोप प्लान बनाएये । होता क्या हैं कि एक आध चीज का दाम जब बढ जाता है तो किसान उस फसल के पीछे दोडने लगता है, फिर दूसरी फसलों की कमी होती है । तो जो हमारी आवश्यकताए हैं उन आवश्यकताओ का ख्याल करते हुए पूरे देश के लिए दीर्घकालीन फसल की योजना बनाई जाये बीमे की योजना भी

किसानो के लिए बनाने का समय आ गया है। अकाल बाढ इस के चलते किसान बर्बाद होता जाता है। क्रोप इंशोरेंस की व्यापक योजना बनाएँ। मंत्री महोदय से भी जो सवाल मैंने पूछे थे उन के जवाब मे उन्होने कबूल किया कि पिछले पाच वर्षों मे गेहू की पैदावार लगातार बढती गई लेकिन मूगफली, रुई, दाल चढा होता है और पैदावार नही बढ रही है। जिस महाराष्ट्र राज्य की तारीफ की जाती है क्या मंत्री महोदय इस बात से इंकार कर सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रस्थापित होने के बाद 10, 11 साल के अन्दर महाराष्ट्र मे खेती की पैदावार 14 प्रतिशत घट गयी और अनाज की पैदावार 18 प्रतिशत घट गई। तो आप लोग कृषि के विकास की कोई समुचित योजना बनाइये वर्ना यह देश रसातल में चला जायगा।

पिछले तीन, चार साल से जो गलत नीतिया चल रही थी उस का असर इसलिये लोगो के सामने नही आया कि पश्चिमोत्तर भारत मे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे और आस पास के इलाको मे किसान गेहू की पैदावार बढाता गया इसलिये इन की सारी गलत नीतियो पर चादर बिछाने का काम हुआ। एक साल अकाल पडा, थोक व्यापार का इन्होने नाटक किया। और आज सारी स्थिति आप के सामने है। तो मंत्री महोदय मेरे इन सारे मुद्दो का अपने भाषण मे इन बातो का उत्तर देने की कृपा करे।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मदसौर) सभापति जी, सरकार की गलत कृषि और आर्थिक नीतियो के कारण जिन चीजो को किसान पैदा करता है जो किसान की आवश्यकता की चीजे हैं उन की कीमतो में भारी अन्तर है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि गये तीन सालो मे किसान की औसत आमदनी मे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा किसान के उपयोग मे आने वाली चीजो के दाम मे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो मेरी जानकारी है उस के अनुसार यह अन्तर लगभग 50 से 70 प्रतिशत तक का है। मै जानना चाहता हू सरकार ने इस अन्तर को मिटाने की दृष्टि मे क्या कदम उठाये है ? यद्यपि सरकार ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशो के आधार पर हम किसान को गेहू, धान का मूल्य देते है। लेकिन क्या यह मूल्य वर्तमान मे बढती हुई कीमतो की दृष्टि से उपयुक्त है और क्या सरकार गेहू, धान तथा गन्ने के मूल्य को बढाने का विचार रखती हे? अथवा क्या कृषि मूल्य आयोग ने आज की स्थिति मे इन कीमतो पर विचार किया हे ?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram) Mr Chairman, Sir, the mills use jute as raw material for manufacturing jute products In West Bengal, jute is sold at Rs 30 to 32 per maund

Within 15 days, the price of jute has come down from Rs 45 to 30 and there is no party between the raw jute and the manufactured jute products I would like to know from the hon Minister whether Government is going to fix the price of jute at Rs 80 per maund to save the jute growers of our country and issue instructions to the Jute Corporation of India to purchase all the jute at the rate of Rs 80 per maund from the villagers and open procurement centres in the villages?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) सभापति जी, ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के मुकाबले पर दूसरी ऐसी कौन सी आप की संस्थाये है जो यह बताती है कि गेहू का मूल्य यह मिलना चाहिये ? मेरा ख्याल है कि भारत मे ऐसी

[श्री मूल चन्द डागा]

आप की कई संस्थायें है जो ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन रेट तय करती है उन मे काफी फर्क होता है । जैसे पंजाब के अन्दर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने जो प्राइस बनायी है और जगह भी ऐग्रीकल्चर इंस्टीटयूट है उन्होंने जो प्राइस बतायी है, तो उन दोनो द्वारा बतायी गयी प्राइसेज मे फर्क क्यों है ?

दूसरा मेरा सवाल है देश के अन्दर 5 एकड से कम का कितने काश्तकार है और उन को आप के बैंको से कितना लोन मिल गया है ?

तीसरा सवाल यह है कि आप के यहां पर आज डीजल, सीमेंट तथा और जो उस के काम आने वाली चीजे हैं, किसान की उपज के दाम की तुलना में इन चीजो के जो दाम बढ गये है उन का मुकाबला किसान कर सकता है ? इसके लिये सरकार अगले टाइम मे क्या करने जा रही है ?

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) सभापति जी, मंत्री जी ने प्रश्नो का जवाब [illegible] जिस भावना से सवाल पूछे गये थे, उस का टाल कर दूसरे जवाब दिये गये है । इन के जवाब से कुछ ऐसे मुद्दे पैदा होते है जिन का जवाब मैं मंत्री जी से चाहूंगा ।

आप ने कहा कि डिमान्ड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होती है । क्या हम इसी बात को कायम रखना चाहते है कि ऐग्रीकल्चर प्राडक्शन की सप्लाई और डिमान्ड कितनी है उसी के हिसाब से प्राइस फिक्स करते जायेंगे और आपिन मार्केट को आपिन छोड देंगे, जो कि हमारी पालिसी नहीं है । उस से काश्तकार क्या तबाह नहीं होगा ? मैं कहना चाहता हू कि ऐग्रीकल्चर प्राड्यूस जो रा-मैटीरियल है उसी को फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिये काम मे लाया जाता है, दोनो की कीमत मे जमीन आसमान का अन्तर होता है । आप रुई को ही ले, गेहू को ले, एक किलो रुई की कितनी कीमत काश्तकार को मिलती है ? और उस से जो फिनिश्ड गुड्स बनती है उस की क्या कीमत होती है, और कितना उस का लेबर और प्रौफिट का मार्जिन रखा जाता है । इन दोनों में कोई आप पैरिटी रखना चाहते है या नही ? जब तक इस पैरिटी को आप नही रखोगे तब तक ब्लैक मनी की इकोनामी बढती जायगी और उस से डिसबैलेंस पैदा होगा । इसलिये रा-मैटिरियल की प्राइस और उस से बनने वाली फिनिश्ड गुड्स मे पैरिटी होनी चाहिये

आप ने कहा कि ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिश के हिसाब से प्राइस फिक्स करते है । माफ कीजिये, मै कहना चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन मे तीन शब्द है, उस मे बैठने वाले मेम्बर प्राइस और कमीशन, यह दो शब्द तो जानते हैं, लेकिन ऐग्रीकल्चर से उन का कोई लेन देन नही है । एग्रिकल्चरिस्ट की क्या डिफिकल्टीज होती है कितनी उसकी कास्ट प्राइस होती है इसको कतई नही जानते है । मे जानना चाहता हू कि ऐसी स्थिति मे क्या आप एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन को [illegible] रखना चाहते है या नही ?

ह्वीट का जो प्रोक्योरमेंट सीजन था वह खत्म हो गया है । आज स्थिति यह है कि गांवों मे लोग गेहू को मवेशियो के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे है और चना जो मवेशियो का चारा है उसको बेच रहे हैं । इस प्रकार की स्थिति आगे न पैदा हो और ह्वीट का जब साइंग सीजन आए उस मे पहले पहले ह्वीट की प्राइस घोषित करेंगे ? यह एक बहुत बडा चैलेंज है । आने वाले साल मे ह्वीट एरिया बहुत रिड्यूस हो जायगा और कही हमारी इकानोमी शैटर न हो जाए, इसके बारे मे भी क्या गवर्नमेंट कुछ सोच रही है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P SHINDE) I am glad that Shri Madhu Limaye and a

number of other colleagues hase raised an issue which needs to be debated at the national level. Obviously, in this country, for some time to come, we shall have to depend and coninue to depend on agricultural production for the prosperity of the country and for the development of our economy. Therefore, amongst all the factors which will affect agricultural production favourably or unfavourably, one of the most important is the price policy. The price policy is going to determine the shape of development of agricultur in our country. As far as this aspect of the problem is concerned, I entirely agree with the hon. Member that our approach should be to evolve sound price policies as far as agricultural commodities are concerned.

Then, naturally the issue arises whether *vis-a-vis* the organised industry, agriculture and agricultural trade stand in an unfavourable position. Therefore, this matter really needs some explanation, and I would like to explain Government's point of view and policy in regard to these matters.

A point has been raised by hon. Members, namely whether possibly we can have a parity of prices between industrial goods and agricultural commodities. I can only say that this is really a very complex subject. In a number of other countries, the same exercises have been made. I quite see the rationale of it broadly, because ultimately there is the need for parity not only as between industrial products and agricultural commodities, but to my mind there is even need for parity between various agricultural commodities themselves, because as the hon. Member himself has pointed out, when distortions develop in Agricultural commodities, a shift in crop patterns or crop acreages may take place, if the parity is not maintained.

For instance, take this year. We have taken over the trade of wheat. But on course grains, there is no control, and this may lead to certain distortions if further consequential action is not taken or due notice is not taken of the present price distortions which have come in the agricultural economy.

As far as broad partiy of price structure is concerned, I think that we shall in times to come have to establish that parity, but when we come really to the question or determining the parity, then it becomes a very complex problem. The US Government from 1910 onwards had tried to work on these lines, and a number of other countries also have tried to study this. But we have to study the problem in our own context taking into consideration our own situation. I can only say that recently the Ministry of Agriculture has been seized of this matter, and we propose to entrust this matter to the National Commission on Agriculture, namely what should be the broad principles which should be observed in evolving the price structure of vari our agricultural commodities. I propose to entrust this to the National Commission on Agriculture in a week's time or so, so that the commission may go into this make appropriate recommendations to the Government of India, because the commission when they go into these problems of individual prices of individual commodities will be in a position to follow certain broad guidelines and perhaps parity will be one of the factors which can be taken into consideration.

The hon. member referred to Japan. I have also had occasion to study some of the problems connected with the price policies of the Japanese Government. I quite see that once Japan was a deficit country in foodgrains. But by relentlessly pursuing an incentive price policy, they have succeeded in making their country surplus. Here again there is a big if or but, because the Japanese economy is predominently an industrial economy. For instance, they purchase rice at a very high price and sell it at a

[Shri Annasaheb P. Shinde]

very cheap price; they subsidise it very heavily because their economy is in a position to subsidise and incur very heavy expenditure on subsidy. Whether we can do it under our own conditions is again a matter that can be a subject of dialogue. But there can be no disagreement with the basic principle which is involved there, that we must have an incentive price policy. That is as far as the broad approach is concerned. (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN: No, no. He need not answer Shri Nayak.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: As far as the Government of India's approach is concerned, as you yourself are aware, for years we have no policy. Even the prices which were fixed before 1966 or 1964 were more or less on an arbitrary basis. Later on we began to take the advice of competent bodies The Government of India decided to appoint the Agricultural Prices Commission. This Commission got into the problems of the prices of individual commodities and make their recommendations which are submitted to the Chief Ministers Then the Government of India comes to certain conclusions.

But our experience is that even this is not enough. Therefore, Government have taken the next very important step. We have now set up a very elaborate machinery all over the country for working out comprehensive data of the cost of production of the principal commodities. This was never before done in the country. It is a vast machinery which has been set up, just as we have a machinery for working out the cost index for the working class. Even though it has some shortcomings and weaknesses, it helps us to work out certain broad policies. So similarly we are having this comprehensive machinery for collection of cost of production data for the principal agricultural commodities.

We have received the first data for the first time,. This is being processed because the data are very voluminous. In future, the Agricultural Pricess Commission will have certain basic data to work out the cost of production figures. So long the exercise of the Agricultural Prices Commission was based on commonsence, advice of State Governments and certain statistics furnished by universities, but henceforward, it will be much more scientific data and these data would be used for determining the prices of agricultural commodities.

If we have the broad principles which we are now going to have from the National Agricultural Commission, I think we will have quite a sound policy for determining the prices. First of all, we have the Commission. What should be the composition of the Commission can be a matter for argument and Government have an open mind on that. Secondly, there is the cost of production of cultivation.

SHRI MADHU LIMAYE: How many agriculturists have been appointed to the Agricultural Prices Commission?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Thirdly, we will have new broad principles which will provide the basis for determining the prices of agricultural commodities.

Shri Limaye has asked about the representation of agriculturists on the Commission. In fact, this point has been raised a number of times on the floor of the House. At one stage when the late Shastriji was there members had insisted that Government take an immediate decision on this. When we examined it, we found that this preposition was beset with a lot of difficulties. I am not opposed to it. But if there is representation of farmers, then consumers will say that they must have some representation; other sectional interests may perhaps claim representation. So it is not a simple preposition. Already there is a panel of agriculturists; it is an advisory panel which advises the Agricultural Prices Commission. There are farmers and some MPs who are farmers on this panel. The Commission naturally take into consideration the recommendations and advice of this panel before coming to conclusions.

But I am prepared to concede that this shortcoming is there in the system. There is need to improve it, and perhaps a debate like this may help us to improve the system as such. We are becoming a mature nation and I am quite sure, as and when we are gaining more and more experience we shall be in a position to evolve a very sound and appropriate price policy.

I would concede that as far as the Government of India's approach is concerned, as I have already replied, while replying to the unstarred question, an element of speculation does come in in agricultural commoditions, particularly the seasonal fluctuations. In this process, who are exploited? It is particularly the small farmers who are exploited in this process because they have no holding capacity. We can study this phenomenon This year is an unusual year, but take the history of the last forty or fifty years or even a century. You will find that in the immediate post-harvest period, that is, after the harvest, there is a sudden fall, and again, in the lean period there is a sharp increase in prices. That means both the producers and the consumers are exploited by the same category of persons like the speculators who operate in the agricultural plane. Therefore, the Government of India have decided to proceed in the direction of the take-over of the wholesale trade in some important commodities. One can criticise whether it is right or wrong, but I think this is one of the efforts to eliminate the element of speculation. Therefore, I think the Government of India is taking very desirable steps in this direction.

I can only assure the hon. Member that our effort would be, in times to come, to attend to this problem of parity so that there is nodistortion in the economy. As far as the agricultural economy is concerned, the country's economy is proceeding on a sound basis. As far as the individual crop problems are concerned,—jute, tobacco, or cotton— I think all these crops will require attention from the same angle. Therefore, I would not like to go into the problem of individual crops.

SHRI MADHU LIMAYE: Crop insurance.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Our country earns the largest amount of foreign exchange from jute production and the price of jute has come down at the cost of the jute producer.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I can only submit, reply to the query you have raised, that in this country, in the field of marketing agricultural produce, there was practically anarchy. There were many problems; there was no institutional framework to protect the interests of the farmers Now, we have Cotton Corporation, the Jute Corporation and the Food Corporation. We have a number of other corporations. The purpose of the Government of India is to see that by having these very powerful national organisations we are in a position to protect the interests of the producers. In the case of jute, we propose to protect the interests of the jute producers also by providing them marketing facilities and a minimum price support. Whether it will be 73, 74 or 80 is a different matter. But the Government of India's approach is to protect the interests of the small producers, so that the country's economy gets more and more strengthened.

[Shri Annasaheb P Shinde]

These are the observations which I wanted to make I am thankful to the hon Member for having raised this debate

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय गेहू धान आदि के दामो मे कोई वृद्धि नही हुई है लेकिन कृषि उपयोगी सब चीजो के दाम 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ गये है। गेहू, धान व गन्ने के दाम बढाने के बारे मे सरकार का क्या विचार है ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE. I can only say that our approach —to what extent I am in a position to satisfy you is a different matter—would be to see that incentive prices are given to the producers.

18.56 hrs.

STATEMENT *RE* DEMONSTRATION OUTSIDE THE OLD SECRETARIAT BUILDING DELHI

THE MNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K C PANT) Sir, On 27th July, 1973, about 600 persons had assembled to demonstrate outside the Old Secretariat Building The Metropolitan Council was in session. At about 4 00 P M., when their leaders were inside the building some persons tried to forcibly enter the area, the entry into which is regulated by passes Considerable pressure was also built up against the gate Some of the demonstrators were also reported to have indulged in stone throwing The police resorted to teargas to prevent forcible entry of the demonstrators into the area A magisterial inquiry has been ordered into the incident

18 58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday August 2, 1973/Sravana 11, 1895 (Saka)
